(ग) छोटी कागज मिलों अर्थात् 2000 टन क्षमता के लिए 75 प्रतिशत, 2000 से 5000 टन क्षमता के लिए 60 प्रतिशत और 5000 से 10000 टन क्षमता के लिए 50 प्रतिशत की तरह की 3,000 टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली छोटी ग्रौटोमैटिक बोर्ड मिलो के लिए शुल्क मे 75 प्रतिशत छूट न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जिन छोटे निर्माताओ की पिछले वर्ष में निकासियां, 5 लाख रुपये की प्रथम निकासियो पर देय शुल्क से 15 लाख रुपये से अधिक नही थी, उन्हे प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने 1978 के बजट प्रस्तावो के अनुसरण मे 69 निर्दिष्ट वस्तुओ के निर्माणकर्ता छोटे एकको को छूट दी है। परन्तु ग्राटोमैटिक मिल बोर्ड और [illegible] बोर्ड मिलो के मामले में भारत सरकार राजस्व विभाग की 16 मार्च, 1976 की अधिसूचना संख्या 70/76 के० उ० शु० द्वारा उत्पादन शुल्क से छूट की एक अलग योजना प्रदान की गयी हैं ।

(ख) प्रश्न का ग्राशय स्पष्ट नही है । वर्तमान बजट में विशेष उत्पादन शुल्क लगाने के परिणामत, लगने योग्य मूल शुल्क के 1/20 भाग को छोड़ कर कागज और गत्ते पर शुल्क में कोई वृद्धि नही हुई है, यह शुल्क बड़ी और छोटी दोनो बोर्ड मिलो पर लागू होता है ।

(ग) छोटी कागज मिलो का जिन कारणो से शुल्क में य रियायत दी गयी है वे ग्र य बातो के साथ-साथ लागत संबधी घाटे हैं जो छोटी कागज मिले अपेक्षाकृत बड़ी कागज मिलो के मुकाबले उठाती है । छोटी ग्राटोमैटिक बोर्ड मिलो के मामले मे, इस प्रकार के घाटे बड़ी बोर्ड मिलो के मुकाबले प्रभावी रूप से प्रमाणित नही हुए हैं ।

टाटा कम्पनी जमशेदपुर (बिहार) पर करों की बकाया राशि

6049. श्री ग्रार० पी० दासगुप्ता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाटा कम्पनी जमशेदपुर, बिहार पर 1 मार्च, 1978 को करो की कितनी राशि बकाया थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह): इस प्रश्न का सम्बन्ध सभवत टाटा ग्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड से है, जिस का मुख्यालय जमशेदपुर में है। 1-3-1978 की स्थिति के अनुसार, इस कम्पनी पर 17 91 लाख रुपये की सकल मांग बकाया थी। यह मांग विवाद ग्रस्त है और अपील का निपटान होने तक इसे रोक दिया गया है ।

ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत

6050. श्री राम कंवार बेरवा: क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि क्या दातवाला समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार करते हुए ग्रामीण बैंक कर्मचारी सघ के प्रतिनिधियो से श्रमिक समस्याग्रो पर बातचीत की थी तथा इस बारे मे क्या प्रगति हुई है ग्रौर यह प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित होगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : चूकि कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी सघ नही है, इसलिए दातवाला समिति ने ऐसे किसी सघ से बातचीत नही की। 23-2-1978 को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई दातवाला समिति की रिपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी के सीधे सरकार को शीघ्र उपलब्ध होने की सम्भावना है ।